खंड ६ संख्या ४

बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि १९ फरवरी १९६४ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य :

Government Statement regarding call-at ention notice:

संक्रामक रोग चिकित्सालय, पटना सिटी में दवा की चोरबाजारी ।

BLACKMARKETING OF MEDICINES IN INFECTIOUS DISEASES HOSPITAL, PATNA CITY.

श्री रामानन्द तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्रामक रोग चिकित्सालय जो पटना सिटी में है उसमें कितना भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसका मैं कुछ प्रमाण देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि आये दिन बिहार की गरीब जनता जो टैक्स देती है उसके पैसे किस तरह से दुरुपयोग किये जाते हैं। दिनांक २३ नवम्बर १९६३ को अध्यक्ष महोदय, देखा जाय दवा पांच रोगियों के नाम में एक ही रजिस्टर में मुंशी, बिन्दी, कुन्ती देवी, सीता-मनी और समसुदमी करके दिखलायी गयी और यह विचार किया जाय कि २३ तारीख को जबकि पेसेन्ट एडमिट होता है तो फिर पांच रोगियों के नाम पर बोगस दवा जिसकी कुल कीमत ७५ रु० को दर से ५०० रु० से भी अधिक होती है वे सभी किस प्रकार खतम कर दी गयीं। तिथि २४ नवम्बर १९६३ को सुपरिन्टेंडेंट, ब्रजवंशी बाबू को इस संबंध में जिसने खबर दी उसे डांट पड़ती है और वह पुलिस में खबर देने चला जाता है। २८ तारीख को

अध्यक्ष—जैसा कि माननीय सदस्यों को सूचना दी गयी है, बजट भाषण की प्रतियां बाहर में वितरण -पटल पर उपलब्ध होंगी। माननीय सदस्य अपनी सुविधा के साथ उसे ले लेंगे। अब राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति जो धन्यवाद-ज्ञापन का प्रस्ताव है उस पर वाद-विवाद चलेगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

DEBATE ON GOVERNOR'S ADDRESS.

*श्री रामसेवक सिंह—अध्यक्ष महोदय यहां की बढ़ती हुई बेरोजगारी की खतरनाक स्थिति की ओर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। हाल में राज्य ट्रांसपोर्ट में कुछ जगहों के लिए विज्ञापन हुआ, उसमें जगह कम थी और पांच-छः हजार तक बी० ए०, एम० ए० के विद्यार्थी आए। उनके बैठने की व्यवस्था तक नहीं हो सकी, कोई कुर्सी लेकर भागने लगा, कोई कागज लेकर भागने लगा। आज बेरोजगारी सारे बिहार में व्याप्त है। आज जो बहाली होती है उसमें योग्य उम्मीदवार इधर से उधर घुमा दिए जाते हैं और जो मंत्री के लोग होते हैं, जो उनके संबंधी होते हैं, जो उनके नजदीकी के आदमी होते हैं उनको उस जगह पर ले लिया जाता है। जैसे शौर्टहैंड या टाइपवाले आदमी के लिए जो जगह है उसमें देखा गया है कि जो शौर्टहैंड नहीं जानते हैं वैसे लोगों को नियुक्त किया गया और जो जानते हैं वे मारे फिरते हैं। इस तरह की नियुक्ति भी भ्रष्टाचार का जड़ है।

अलाभकर खेती के लिए मालगुजारी माफ कर देते, लेकिन इसका भी राज्यपाल के भाषण में जिक्र नहीं है। अगर राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र रहता तो किसान खिल उठते। जिस किसान को एक कट्ठा, दस कट्ठा या बीघा, दो बीघा जमीन हो जिससे उसका लाभ नहीं होता है, उससे केवल उसका खाना-पीना भर चलता है वैसी जमीन की मालगुजारी माफ हो जानी चाहिए थी। ६¼ एकड़ से कम जमीनवालों की मालगुजारी माफ कर दें तो आपको ज्यादा का नुकसान नहीं, सिर्फ रुपए में दो नए पैसे का घाटा होगा जिसे आसानी से दूसरी मद से पूरा कर सकते हैं।

अनिवार्य शिक्षा पद्धति के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र नहीं है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा देंगे, लेकिन हर जगह देखने को मिला कि पैसा लगता है। कहा गया था कि सातवें वर्ग तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जायगी, लेकिन, उदाहरण के लिए खगौल में जो घनश्याम बालिका विद्यालय है वहां पहले वर्ग के विद्यार्थी से भी दो रुपये, डेढ़ रुपया और एक रुपया आदि के हिसाब से लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि मैट्रिक तक सारे बिहार की जनता को मुफ्त शिक्षा मिले।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संकेत मिला है कि पिछड़ी जाति को, हरिजनों को, छात्राओं को, आदिवासियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि गत साल बैठक करके अपने जिले के जिन लड़कों के लिए हमलोगों ने सिफारिश की उनको आजतक एक पैसा नहीं मिल सका है। वे विद्यार्थी हमलोगों के पास आते हैं और कहते हैं कि आपलोग झूठ बोलते हैं, हमको सरकार की ओर से एक पैसा भी नहीं मिला, लेकिन इस तरह का संकेत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे चूंकि यह गरीबों की बात है।

आज कहा जाता है कि लड़कों में अनुशासन हो, बहुत साथियों ने इस पर प्रकाश डाला है, पर सवाल है कि यह अनुशासनहीनता क्यों फैल रही है ? आज स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हर जगह में तिकड़मबाजी चल रही है, वे कौन गुट के हैं, हम कौन गुट के हैं यह आवाज है तो विद्यार्थी इससे कैसे बच सकते हैं। नतीजा यह होता है कि विद्यार्थी भी अपने को बांध नहीं सकते हैं। जब से ये शिक्षा मंत्री अपने पद पर आये हैं तभी से सारे बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच अराजकता फैल गयी है। कहीं छूरेबाजी हुई है तो कहीं सर फूटे हैं।

अब मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान अराजपत्रित कर्मचारियों की ओर ले जाना चाहता हूं कि वे इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। कोई भी हुकूमत अपने कर्मचारियों की मां होती है, इसलिये यदि बच्चे अपने मांग को लेकर मां के पास जाते हैं तो मां का यह कदापि कर्त्तव्य नहीं होना चाहिये कि वह अपने बच्चों को बेरहमी के साथ ठुकरा दे। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस श्री रेवती कान्त सिंह, सहायक को आपने ससपेंड किया है, उसपर गंभीरतापूर्वक विचार कर उस कर्मचारी को पुनः अपने काम पर वापस आने का आदेश दें। आज सारे बिहार में किस तरह से महंगी बढ़ रही है कि मुझे डर लगता है कि यहां भी बंगाल की हालत न हो जाय कि लाखों आदमी फूटपाथ पर भूखे मरें। हमलोगों का जो अपने ऊपर बीत रहा है, वे जानते हैं। फिर गरीब कर्मचारी और चपरासियों पर क्या बीतता होगा। आज बहुत-से ऐसे मजदूर हैं जो आधा पेट खाना खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को जल्द-से-जल्द गंभीरतापूर्वक विचार कर बढ़ती हुई कीमत को बांधना चाहिये।

अब मैं अबरख के बारे में कहना चाहता हूं कि हाल ही में जब मैं मुंगेर तिलैया गया था तो पता चला कि बड़े व्यापारी लोगों ने अपना माल भेज दिया जबकि केन्द्रीय सरकार की ओर से माल बाहर भेजने के लिये मना किया गया था, लेकिन ये चालाक व्यापारी क्यों मानें ?

अब मैं शाहाबाद जिले के नासिरगंज की एक बात कहना चाहता हूं जिसे ट्रेजरी बेंच के सभी लोग जानते होंगे। वहां पर श्री राम एकबाल सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और वे थाने में जाकर वहां से रजिस्टर लेते हैं और हर जगह मीटिंग करते हैं। वे पटना में प्रेस कांफ्रेंस करते हैं परन्तु १० तारीख को कुर्की होती है, जब वे हर जगह आते जाते हैं। तो कुर्की क्यों हुई ? उनका बैल जब्त कर लिया गया, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे संयुक्त परिवार में रहते हैं। बैल को काइन हाउस (Kine House) में सड़ा दिया गया, इससे वह किसी काम का नहीं रह गया है। मगर उनका क्या दोष था ? श्री राम नरेश महतो की हत्या हुई। निर्दोष व्यक्ति को जेल में जान से मार दिया गया। आज हर जगह चोरी-उकैती बढ़ रही है। उनका कहना था कि हत्या की जांच होनी चाहिये।

जापानी खेती का नाम हम पहले सुनते थे। इसमें करोड़ों रुपये खर्च किये गये, परन्तु अब इसका नाम भी नहीं है। अब सघन खेती की बात कही जाती है। इसके लिये १६ कुएं १६,००० रु० खर्च करके बनाये गये। मगर अफसरों के घूमने में, गाड़ी, पेट्रोल में करीब साढ़े ३ लाख रुपये खर्च हुए हैं। इस प्रकार पैदावार नहीं बढ़ेगी। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। जिस काम के लिये अफसर बहाल हों, उन्हें उस काम की निगरानी करनी चाहिये। उन्हें किसानों से मिलकर उनकी दिक्कतों को जानना चाहिये। हमलोगों से राय लेनी चाहिये। हमलोगों की राय को लेकर अपने कार्यक्रम में सुधार करना चाहिये। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। मुख्य मंत्री के हाते में अरहर के मोटे-मोटे पौधे हैं। उनको अनुभव है कि खेती कैसे होती है। इसलिये उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि हमारी पैदावार कैसे बढ़ेगी।

आज सरकार को देखना चाहिये कि हमारे बगल में बैठने वाले दो सदस्य मजदूरों की मांग को लेकर अनशन करने जा रहे हैं, परन्तु सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है। अराजपत्रित कर्मचारियों की बातें नहीं सुनी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। यदि वह कुछ भी विचार नहीं करती है तो मुझे भी लाचार होकर अनशन करना पड़ेगा।

श्री जनार्दन तिवारी---अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि राज्यपाल महोदय ने

अपने अभिभाषण में इस राज्य की सबसे जटिल समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है और उसकी चर्चा भी नहीं की गयी है। राज्यव्यापी भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार के सामने कोई योजना नहीं है। हमारे राज्य में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। भ्रष्टाचार फैलने का कारण यह है कि इन मंत्रियों में पूर्णरूप से भ्रष्टाचार है और वे इसे प्रोत्साहन देते हैं।

डा० बी० एन० राय जो इंडस्ट्रीज विभाग के टेकनिकल सेक्शन में थे उन्हें भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने वहां से निकाल दिया क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का अभियोग था। अभियोग लगाने के बाद वे टेकनिकल स्कूल दरभंगा में गये। वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया और हाई कोर्ट में केस किया। जब उन्होंने समझा कि उनको सजा हो जायगी तो केस को वियड्रा कर लिया। बाद में मुख्या मंत्री बदल गये। इसका नतीजा हुआ कि उनको जमशेदपुर इंस्टिट्यूट में १,६०० रु० वेतन देकर रखा गया है। अब इसी विभाग में लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वे वहां १,६०० रुपया पा रहे हैं तो क्या कारण है कि वे उस जगह को छोड़ कर यहां १,००० रुपया पर बुलाये जा रहे हैं। आखिर ६०० रुपया का घाटा वे क्यों सह रहे हैं? यह बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अफसर को क्यों राज्य में लाया जा रहा है? मैं समझता हूं इसमें प्रमुख हाथ हमारे मुख्य मंत्री का है, उन्होंने बार-बार यह कहा है इस प्रान्त से भ्रष्टाचार मिटा देंगे लेकिन वे इस करप्ट अफसर को नाजायज ढंग से यहां ला रहे हैं। इससे यह नहीं मालूम होता है कि भ्रष्टाचार इस प्रान्त से मिटने को है। भ्रष्टाचार प्रशासन में जकड़ गया है और इसके चलते जो दिन प्रतिदिन हो रहा है वह हमलोगों के सामने प्रत्यक्ष है। छपरा के श्री बी० पी० श्रीवास्तव जो वहां सिविल सर्जन हैं वे बहुत ही करप्ट आदमी हैं, जब वे सहरसा में थे तो वहां भी उनपर केस था, जब वे आरा में थे तो उनपर वहां भी बलात्कार का केस था, हुजूर, वे इस तरह के करप्ट अफसर हैं। जब से वे छपरा में सिविल सर्जन होकर आये हैं तो वहां के लोगों के लिये हेडेक बन गये हैं। वहां के भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह यादव ने इसके सम्बन्ध में एक आवेदन-पत्र दिया था लेकिन आजतक उसपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। वे इतना भ्रष्ट हैं कि नाजायज ढंग से जो ब्लॉकों में हेल्थ विजिटर्स रहती हैं उनके साथ वे अन्याय करते हैं, दुराचार करते हैं।

*श्री कृष्णबल्लभ सहाय---अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन होगा और जैसा कि मैंने

पहले भी इसका जिक्र किया है कि सरकारी अफसरों के विरोध में अगर कुछ कहा जाय तो स्पेसिफिक एलिगेशन हाउस में कहें, इससे हमें सहायता मिल सकती है लेकिन आप जेनरल बात बोलते हैं तो इसपर जांच करने में दिक्कत होगी और कहां कहां खोजते चलें कि कौन औरत है। अगर आप स्पेसिफिक एलिगेशन दें तो इससे मर्यादा बढ़ेगी लेकिन जनरल एलिगेशन से तो मर्यादा नहीं बढ़ सकती है।

अध्यक्ष—जैसा कि माननीय सभा-नेता ने कहा, मैं भी यह उचित समझता हूं कि जो अभियोग हो तो उसके साथ पर्याप्त तथ्य हो ।

श्री जनार्दन तिवारी—उस पर जो अभियोग लगाये गये हैं वे सभी श्री जयपाल सिंह यादव ने लिख कर इन्हें दिया है ।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मुझे ऐसा कोई आरोप नहीं मिला है ।

अध्यक्ष—मैं एक निवेदन माननीय सदस्यों से भी करना चाहता हूं कि सदन में आपको बोलने का प्रिविलेज है लेकिन संयम से बोला कीजिये तो ज्यादा अच्छा होगा । प्रिविलेज पर नहीं, किन्तु आप पर केवल संयम का बंधन चाहता हूं ।

श्री जनार्दन तिवारी—अध्यक्ष महोदय, बात है कि इतना वे लोग भ्रष्ट हो गये हैं कि हमलोग अपना पेशेंस लूज कर देते हैं ।

अध्यक्ष—आप पेशेंस लूज करते हैं और मुख्य मंत्री को कहते हैं कि गंभीरतापूर्वक विचार कीजिये ।

श्री जनार्दन तिवारी—अध्यक्ष महोदय, ये जो अराजपत्रित कर्मचारियों की मांग है बहुत दिनों से चली आ रही है । १६ वर्षों से वे लोग अपनी मांग पर डटे हुए हैं लेकिन उसपर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ । उन लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री को एक सुझाव दिया है और उनका कहना है कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिये लोगों पर अलग से कर लगाना पड़ेगा लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूं । आज इस प्रशासन में जो नाजायज खर्च होता है उसको अगर बचाया जाय तो कम से कम ११ करोड़ रुपये की फिजूलखर्ची को रोका-जा सकता है और इसका सदुपयोग उन कर्मचारियों के लिये आप कर सकते हैं । मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की फिजूलखर्ची को दूर करें और जो उनकी मांग है उसपर विचार किया जाय । यह बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष—मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगे बजट पर विवाद होगा और फिजूलखर्ची की परिभाषा देनी होगी कि किसकी समझ से फिजूलखर्ची क्या है और आप अगर ऐसा आंकड़ा दीजिये तो उसपर सरकार विचार करेगी ।

श्री जनार्दन तिवारी—तो उसपर विचार किया जायगा । अध्यक्ष महोदय, एक और सुझाव है । खास कर इस प्रांत में ये जो पाकिस्तानी मनोवृत्ति के लोग व्यापक रूप से फैले हुए हैं उनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ऐसे लोगों पर सरकार जरा उचित और कड़ी कार्रवाई करे । ऐसा देखा जाता है कि बहुत-से ऐसे अफसर हैं जो इसी सचिवालय में हैं, जिनका मैं नाम गिनाऊंगा लेकिन अभी नहीं ।

कुछ माननीय सदस्य—नाम बतायें ।

श्री जनार्दन तिवारी---मैं नाम बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। लेकिन उनपर उचित कार्रवाई करें और ध्यान दें। बहुत-से ऐसे अफसर हैं जिनका सम्बन्ध सीधे पाकिस्तान से है, वे बहुत-सी बातों को यहां से पाकिस्तान भेजते रहते हैं। उनपर सरकार ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, एक दो और सुझाव देकर मैं बैठ जाऊंगा। गोहत्या इस राज्य में बराबर हो रही है, हालांकि इसके लिए कानून बना है किन्तु उसका उपयोग उचित तरीके से नहीं हो रहा है। कानून में जो अवस्था दी गई है उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है और बराबर व्यापक रूप से गोहत्या हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गोहत्या इस राज्य में पूर्णतया बन्द हो जाये तो हिन्दू-मुसलमान की जो लड़ाई अक्सर हो जाती है वह बन्द हो जाय। हिन्दू गौ को गोमाता कहते हैं और कहीं भी इसकी हत्या हो जाय तो हिन्दू जनता काफी बौखला जाती है और इससे व्यग्र होकर कभी-कभी कम्यूनल रायट हो जाता है। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पूर्णरूप से गोहत्या इस राज्य में बन्द हो जाय ऐसा कानून बनाया जाय। मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(अन्तराल।)

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन।

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

उपाध्यक्ष---माननीय राज्य मंत्री कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करें।

श्री नवल किशोर सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर, जिसकी बैठक १९ फरवरी, १९६४ को हुई, सभा की सहमति हो।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है.....

श्री कामदेव प्रसाद सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हमलोगों को इसकी प्रति नहीं मिली है।

उपाध्यक्ष---बंट रही है।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह---इसपर सभा की सहमति लेने के पहले हमलोगों को इसे पढ़ने का मौका दिया जाय।

उपाध्यक्ष---ठीक है। तबतक राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद हो। माननीय सदस्यगण कार्य मंत्रणा समिति की कार्यवाही देख लें तब इस पर मतदान होगा।